राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज., जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0
E-mail-dirminority@gmail.com ddjprdiv123@gmail.com Website-www.minority.rajasthan.gov.in
Phone No. 0141-2711978, 01414-2711983

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री राजस्थान

डॉ. अरुण चतुर्वेदी
मंत्री अल्पसंख्यक मामलात

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा अर्जित उपलब्धियाँ

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

- राजस्थान राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य 08 जिलों के 10 ब्लॉक्स लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़बास, रामगढ़, तिजारा (अलवर), नगर, कामां (भरतपुर), चौहटन (बाड़मेर), हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़), सम, सांकड़ा (जैसलमेर) एवं तीन कस्बे (मकराना, गंगापुर सिटी एवं टोंक) शामिल किये गये हैं।
- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी) के अन्तर्गत राशि रूपये 13328.88 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत कराए जाकर आधारभूत संरचना के 412 निर्माण कार्य यथा- आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूती कक्ष, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त कक्षाकक्ष, प्राथमिक विद्यालय भवन, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय कक्ष, विज्ञान लैब, नर्सिंग कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास भवन एवं आई.टी.आई. आदि करवाये जा रहे हैं।
- साईबर ग्राम योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक 10400 विद्यार्थियों को डिजिटली साक्षर किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक छात्रावास

- मानसरोवर, जयपुर में 100 अल्पसंख्यक बालिकाओं के अध्ययन हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।
- जिला मुख्यालय/ अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास की सुविधा स्वयंसेवी/ शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है। जिसके लिए 1900/- रूपये प्रति छात्र/छात्रा मासिक अनुदान दिया जाता है।
- वर्ष 2013-14 में 25 छात्रावास व 2014-15 में 14 छात्रावास एन.जी.ओ. के माध्यम से संचालित किये गए। वर्ष 2015-16 में एन.जी.ओ. के माध्यम से 33 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।
- जोधपुर, कोटा, रामगढ़ (अलवर) एवं फतेहपुर (सीकर) में छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है।
- एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत ब्लॉक रामगढ़, किशनगढ़बास, कांमा व सम में 6 बालक-बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास भवन तथा टोंक कस्बे के राजकीय यूनानी महाविद्यालय में बालिका छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है।

अल्पसंख्यक छात्रवृति

- **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति** के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 33197 अभ्यर्थियों को राशि रूपये 22.50 करोड़ तथा 2014-15 में 43233 अभ्यर्थियों को राशि रूपये 29.90 करोड़ का वितरण किया गया।
- **मैरिट कम मीन्स छात्रवृति** के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 2769 अभ्यर्थियों को राशि रूपये 6.93 करोड़ तथा 2014-15 में 4150 अभ्यर्थियों को राशि रूपये 11.04 करोड़ का वितरण किया गया।
- वर्ष 2015-16 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत 67035 तथा मैरिट कम मीन्स छात्रवृति के अन्तर्गत 6814 अभ्यर्थियों ने छात्रवृति हेतु आवेदन किया है।
- वर्ष 2014-15 से डीबीटी योजनान्तर्गत छात्रवृति राशि सम्बन्धित पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक A/C में सीधे ही हस्तान्तरित की जा रही है।

अनुप्रति योजना

* अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए अनुप्रति योजनान्तर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1.00 लाख रू. व राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 50,000 रू. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाती है।
* इनके अतिरिक्त IIT, CAT, CLAT, AIEEE एवं IIM आदि परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
* वर्ष 2013-14 में 47 अभ्यर्थियों को रूपये 11.70 लाख एवं वर्ष 2014-15 में 41 अभ्यर्थियों का रूपये 9.90 लाख वितरित कर अनुप्रति योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

व्यावसायिक एवं शैक्षणिक ऋण

* पारदर्शी तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण कर गत दो वर्षों में 10535 व्यक्तियों को 5280.00 लाख रूपए के ऋण व्यवसाय व शिक्षा हेतु वितरित किये गये।
* समय पर ऋण चुकाने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को कारोबारी व शैक्षणिक ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत तथा महिला अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण ब्याज की छूट प्रदान की जाती है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

* राजस्थान आजीविका मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 15 प्रतिशत राशि व सीटों का अल्पसंख्यक युवाओं के लिए चिन्हिकरण कर कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
* RSLDC के माध्यम से 1069 अल्पसंख्यक युवाओं को वर्ष 2015-16 में 148 विधाओं में निःशुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
* दिसंबर, 2013 से मार्च,2014 तक CIDC (निर्माण उद्योग विकास परिषद्) नई दिल्ली द्वारा 1036 अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न 13 विधाओं जैसे पी.ओ.पी., मेट, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, शटरिंग, प्लम्बर, कलमकारी में प्रशिक्षण दिलवाया गया।
* दिसंबर, 2013 से मार्च, 2014 तक RKCL द्वारा 338 अल्पसंख्यक युवाओं को हाफ फीस में तथा 833 अल्पसंख्यक बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया।
* दिसंबर, 2013 से मार्च,2014 तक RUDA द्वारा 270 अल्पसंख्यक महिलाओं को कौशल वृद्धि डिजाइन प्रशिक्षण तथा महिला दस्तकार मिश्रित समूह के तहत प्रशिक्षित किया गया।

मदरसा शिक्षा

* राज्य में कुल 2803 प्राथमिक स्तर के व 309 उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसे पंजीकृत हैं।
* वर्ष 2014-15 के दौरान 40 मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत तथा 16 नये मदरसे पंजीकृत किये गये हैं।
* मदरसों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु 500 कम्प्यूटर वर्ष 2014-15 में क्रय किये गये हैं तथा वर्ष 2015-16 में 1000 कम्प्यूटर क्रय किये जाकर राज्य में 25 से अधिक बच्चों की संख्या वाले समस्त मदरसों को वितरित किये जावेंगे।
* मदरसों को शिक्षण सामग्री के रूप में चार्ट,ग्लोब, ग्रीन बोर्ड एवं फर्नीचर का वितरण किया जा रहा है। गत दो वर्षों में मदरसों में 20 हजार दरी-पट्टी वितरित की गई एवं वर्ष 2015-16 में 40,000 दरी पट्टियाँ वितरित की जावेंगी।
* मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनानतर्गत मदरसा भवन निर्माण हेतु 102 करोड़ रूपये दिये गये हैं।

राजस्थान हज कमेटी

* हज यात्रा वर्ष 2014 में 3985 एवं वर्ष 2015 में 3747 हाजियों के लिए माकूल इंतज़ाम किये गए और हज यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग

* आयोग द्वारा पूरे राज्य में संभाग व जिला स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को राहत मिली है।

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ

* राज्य सरकार द्वारा कब्रिस्तानों की मरम्मत व सुधार हेतु दो करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।
* राज्य सरकार द्वारा वक्फ सम्पतियों की विडियोग्राफी के द्वितीय चरण हेतु 81.73 लाख रूपये व्यय किये जावेंगे।
* मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट 2015 में ''दरगाह नरहड़ का सौन्दर्यकरण'' की घोषणा की गई तथा सौन्दर्यकरण हेतु राशि 316 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

विपिन चन्द्र शर्मा
अतिरिक्त मुख्य सचिव

शकुन्तला सिंह
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव